21वीं सदी में राजनीतिक पुनर्गठन

पवेंद्र सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, रामचंद्र उनियाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

सारांश

राजनीतिक पुनर्गठन का तात्पर्य वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा परिवर्तनों के संदर्भ में राष्ट्रों द्वारा अपनी दीर्घकालिक रणनीतियों, संसाधनों और नीतिगत प्राथमिकताओं के पुनर्गठन से है। 21वीं सदी वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा संरचना में गहन परिवर्तन का कालखंड है। शीत युद्धोत्तर एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था, जिसमें अमेरिका का प्रभुत्व प्रमुख था, अब क्रमशः बहुध्रुवीय शक्ति संरचना में परिवर्तित हो रही है, जहाँ चीन, भारत और अन्य उभरती शक्तियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस परिवर्तन ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के पारंपरिक स्वरूप को चुनौती देते हुए राष्ट्रों को अपनी विदेश नीति, आर्थिक रणनीति, सैन्य संरचना तथा तकनीकी क्षमताओं का पुनर्गठन करने के लिए प्रेरित किया है। यह शोध-पत्र 21वीं सदी में राजनीतिक पुनर्गठन की प्रक्रिया का विश्लेषण अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सिद्धांतों यथार्थवाद, उदारवाद, संरचनावाद तथा जटिल परस्पर निर्भरता के परिप्रेक्ष्य में करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों का सम्मिलित रूप प्रस्तुत करता है। महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय गठबंधनों का पुनर्संरचना, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का पुनर्गठन, डिजिटल तकनीकों का उदय तथा बहुपक्षीय संस्थाओं की बदलती भूमिका इस प्रक्रिया के प्रमुख आयाम हैं। भारत के संदर्भ में यह शोध दर्शाता है कि "राजनीतिक स्वायत्तता", आर्थिक आत्मनिर्भरता, रक्षा आधुनिकीकरण और डिजिटल नवाचार के माध्यम से भारत ने बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप अपनी नीतियों को पुनर्गठित किया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 21वीं सदी का राजनीतिक पुनर्गठन एक सतत और बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसकी सफलता राष्ट्रों की अनुकूलन क्षमता, संस्थागत सुदृढ़ता तथा संतुलित नीति-निर्माण पर निर्भर करेगी।

मुख्य शब्द: राजनीतिक पुनर्गठन, बहुध्रुवीयता, वैश्विक शक्ति-संतुलन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, भारत की राजनीतिक स्वायत्तता

1. प्रस्तावना

21वीं सदी विश्व राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा सुरक्षा नीति के क्षेत्रों में तीव्र परिवर्तन का युग है। इस सदी ने शीत युद्ध के पश्चात एकध्रुवीय व्यवस्था से बहुध्रुवीय शक्ति संरचना की ओर वैश्विक व्यवस्था को बदल दिया है। यह परिवर्तन न केवल राजनीतिक (Diplomatic) और सैन्य क्षेत्रों में हुआ है, बल्कि आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक तथा बहुपक्षीय संस्थागत स्तर पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैश्विक शक्ति संतुलन में इस परिवर्तन को समझना और 21वीं सदी के लिए राजनीतिक पुनर्गठन की प्रक्रिया का विश्लेषण करना आज के अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय नीति-निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है।

*Corresponding Author Email: pavendrasingh118@gmail.com
Published: 21 May 2026
DOI: https://doi.org/10.70558/SPIJSH.2026.v3.i5.45746
Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

वैश्विक शक्ति बदलने के संदर्भ में विद्वान कहते हैं कि पश्चिमी प्रभुत्व की तुलना में आज पूर्वी देशों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो रही है, तथा बहुपक्षीय और जटिल नेटवर्कों से वैश्विक राजनीति संचालित हो रही है। यह शक्ति परिवर्तन "पश्चिम से पूर्व की ओर" चलने की प्रवृत्ति के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें विकसित तथा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका बढ़ रही है(नाई, 2023)।

राजनीतिक पुनर्गठन अब केवल सैन्य शक्ति के अस्थिर संतुलन तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक संरचना, वैश्विक व्यापार संबंध, तकनीकी प्रतिस्पर्धा तथा बहुपक्षीय कूटनीति जैसे आयामों में भी दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए, 21वीं सदी में विश्व व्यापार व्यवस्था में बदलाव के कारण क्षेत्रीय व्यापार समझौतों का उदय हुआ है, जो पारंपरिक बहुपक्षीय व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और नए आर्थिक-राजनीतिक रूपांकन की आवश्यकता को उजागर कर रहे हैं (दास एवं मो, 2025)।

भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण का भी 21वीं सदी में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत ने अपनी विदेश नीति तथा सुरक्षा दृष्टिकोण को बहुपक्षीय सहयोग तथा आर्थिक साझेदारियों के माध्यम से पुनर्गठित किया है। यह रणनीति क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा साझेदारी और वैश्विक शासन में प्रभाव की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए विकसित की जा रही है (राम, 2020)।

इसके अतिरिक्त, विश्व राजनीतिक और सामरिक परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन को पहचानने के लिए कई शोध और लेख प्रकाशित हुए हैं, (गूच, एम. टी. आर., एवं डी. एम. 2015) जैसे कि 21वीं सदी में भारत एवं पश्चिम एशिया के बीच राजनीतिक संबंधों का विस्तृत विश्लेषण, जो यह दर्शाता है कि वैश्विक शक्ति संरचना में क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा साझेदारी का महत्व बढ़ रहा है (कूपर, टी. एल. (2005)।

21वीं सदी का वैश्विक परिदृश्य

21वीं सदी का वैश्विक परिदृश्य निरंतर परिवर्तनशील, जटिल और बहुध्रुवीय शक्ति संरचना से परिपूर्ण है। शीत युद्ध के बाद अमेरिका का एकाधिकार वाला वैश्विक प्रभुत्व अब कम होता जा रहा है और कई नई उभरती शक्ति-केंद्र उभर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक राजनीति में बहुपक्षवाद, क्षेत्रीय गठबंधनों और प्रतिस्पर्धात्मक हितों का स्वरूप बदल रहा है। उदाहरण के लिए, भारत और पश्चिम एशिया के बीच राजनीतिक संबंधों में व्यापक वृद्धि देखने को मिली है, जो आर्थिक, भू-राजनीतिक और सुरक्षा हितों पर आधारित है। यह बहुआयामी शक्ति अभ्यास 21वीं सदी की वैश्विक चुनौती तथा सहयोग के परिदृश्य को रेखांकित करता है। विश्व व्यवस्था में बहुपक्षीय संस्थान जैसे G20 और संयुक्त राष्ट्र को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप सशक्त और जवाबदेह बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे वैश्विक शासन और न्यायसंगत निर्णय-प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिल सके(हार्ट एवं यूनिस, 2017)।

समस्या कथन

21वीं सदी में वैश्विक शक्ति संतुलन के परिवर्तन के कारण राष्ट्रों को राजनीतिक रूप से अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं का पुनर्गठन करना पड़ा है। परंतु यह पुनर्गठन कैसे हो रहा है? कौन-से कारक इसे प्रभावित कर रहे हैं? और किस हद तक ये प्रक्रियाएँ वैश्विक स्थिरता और राष्ट्रीय हितों के संतुलन को प्रभावित कर रही हैं?

इस शोध का मुख्य समस्या कथन इस प्रकार है:

"21वीं सदी में राष्ट्रों द्वारा अपनाया गया राजनीतिक पुनर्गठन किस प्रकार वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक नेटवर्क और सुरक्षा नीतियों को प्रभावित कर रहा है तथा इसका प्रभाव विशेषकर भारत जैसे विकसित होते प्रभावशाली देशों पर क्या है?"

यह समस्या इस बात पर केंद्रित है कि वैश्विक शक्ति और हितों के बदलते परिदृश्य में राष्ट्रीय राजनीति के पुनर्गठन की प्रक्रिया कितनी प्रभावी और परिणाम-कारक सिद्ध हो रही है।

2. साहित्य समीक्षा

(कुह्न, 2023) हाल के वर्षों में स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा दबाव में आ गया है। यह न सिर्फ़ कॉन्सेप्ट के हिसाब से धुंधला है, बल्कि न्यूक्लियर मल्टीपोलैरिटी, नई टेक्नोलॉजी, हथियारों पर नियंत्रण में बढ़ता संकट और "सॉफ्ट" नियमों को बढ़ती मंज़ूरी ये सभी इस पर असर डाल रहे हैं। साथ ही, न्यूक्लियर हथियार वाले देश संभावित अस्थिरता को लेकर उतने चिंतित हैं जितना कोल्ड वॉर के सबसे गंभीर संकटों के बाद से नहीं देखा गया। यह स्पेशल इश्यू स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी के लिए कुछ बड़ी चुनौतियों को साफ़ करने की कोशिश करता है, साथ ही अस्थिरता के जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने और कम करने के लिए नए स्कॉलरली और पॉलिसी से जुड़े तरीके भी बताता है। तीन आर्टिकल और एक कमेंट्री यूएस–रूस की जोड़ी तथा मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी के लक्ष्यों और तरीकों को स्पष्ट करने की प्रैक्टिकल कोशिशों पर फ़ोकस करते हैं (i) यूक्रेन के खिलाफ़ रूस की लड़ाई में नई टेक्नोलॉजी का असर, (ii) यूएस और रूसी नेताओं की आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को कॉम्पिटिशन की एक नई और ख़तरनाक क्षमता के रूप में देखने की सोच, और (iii) क्राइसिस मैनेजमेंट पर शुरुआती चर्चा करके चीन के साथ हथियार नियंत्रण बातचीत शुरू करने की यूएस की संभावित कोशिशें।

(आयरलैंड एवं हिट, 1999) यह पेपर 21वीं सदी में स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस पाने और बनाए रखने में स्ट्रैटेजिक लीडरशिप के महत्व को बताता है। यह दर्शाता है कि ग्लोबल इकॉनमी ने स्ट्रैटेजिक लीडरशिप के तरीकों पर कैसे असर डाला है और उन नए तरीकों पर चर्चा करता है जिन्हें ऑर्गनाइज़ेशन भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अपना सकते हैं। एनालिसिस इस बात पर ज़ोर देता है कि असरदार स्ट्रैटेजिक लीडरशिप न केवल किसी फ़र्म की पर्यावरण में होने वाले बदलावों पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बढ़ावा देने के लिए भी ज़रूरी है।

(सॉन्ग, डब्ल्यू. 2022) 21वीं सदी की शुरुआत से ही चीन ने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए इंटरनेशनल माहौल का फ़ायदा उठाया है। चीन के स्ट्रैटेजिक पॉलिसी बनाने वालों इस कामयाबी का क्रेडिट कुछ हद तक "मौके की स्ट्रैटेजिक खिड़की का फ़ायदा उठाने" को देते हैं। चीन ने इंटरनेशनल माहौल को कैसे देखा और अपनी मैक्रो-स्ट्रैटेजी की कहानी को कैसे बनाया इसका चीन और दुनिया पर क्या असर पड़ा यह आर्टिकल 21वीं सदी से तीन स्टेज में "मौके की खिड़की" की स्ट्रैटेजिक कहानी के विकास को देखता है और चीन के "डिस्कोर्स कोएलिशन" (सरकार, ऑफ़िशियल मीडिया और इंटेलेक्चुअल एलीट) के नैरेटिव टेक्स्ट का एनालिसिस करके मात्रा और कीवर्ड मैपिंग के मामले में इसके असर का पता लगाता है। स्टडी में पाया गया कि चीन की मैक्रो-स्ट्रैटेजिक कहानी मुख्य रूप से ऑफ़िशियल पॉलिटिकल और सेमी-ऑफ़िशियल इंटेलेक्चुअल एलीट द्वारा चलाई जाती है और स्ट्रैटेजिक इरादों के बाहरी दिखावे के बजाय घरेलू पॉलिटिकल सोच को ज़्यादा अहमियत देती है। यह क्लासिकल और मॉडर्न फ़िलॉसॉफ़िकल सोच और मेथडोलॉजी को "शांति बनाए रखना" और "इकोनॉमिक प्रायोरिटी" के दो मुख्य मकसदों के साथ जोड़ती है। 20 सालों में "स्ट्रैटेजिक मौके के समय" के नैरेटिव प्रोडक्शन के ट्रेंड में एक जगह बढ़त और ऊपर-नीचे गिरावट देखी गई है, और इसके नैरेटिव एलिमेंट्स को बेहतर बनाया गया है, आपस में जोड़ा गया है और सीपीसी की मुख्य पॉलिसीज़ के नैरेटिव के साथ अलाइन किया गया है। "स्ट्रैटेजिक मौके के समय" का नैरेटिव घरेलू लेजिटिमेसी बनाने, स्ट्रैटेजिक मकसदों को कुछ हद तक पूरा करने की गारंटी देने और दूसरे देशों को सीखने के लिए सबक देने में एक ताक़तवर तत्व रहा है। ज़ाहिर है, इस नैरेटिव को कई मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

(सुमारोटो, एट अल. 2024) इस स्टडी का मक़सद स्कॉलरली ट्रेंड्स के एक कॉम्प्रिहेन्सिव बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ज़रिए 21वीं सदी में सिविक एजुकेशन के बदलते माहौल का विश्लेषण करना था। मैप्स के रूप में डेटा को असरदार तरीके से विज़ुअलाइज़ करने की इसकी क्षमता के लिए VOSviewer का इस्तेमाल किया गया। एनालिसिस दो ख़ास पहलुओं पर फ़ोकस करता है कीवर्ड्स, टाइटल्स और एब्स्ट्रैक्ट्स पर आधारित रिसर्च में ट्रेंड्स, और देशों में रिसर्च एक्टिविटी का जियोग्राफ़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। नतीजों में सिविक एजुकेशन रिसर्च में आगे रहने वाले टॉप पाँच देशों पर रोशनी डाली गई है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन जिसमें इंडोनेशिया 32वें स्थान पर है। नतीजे दुनिया भर में सिविक एजुकेशन पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेज़ में लगातार डेवलपमेंट की ज़रूरत पर ज़ोर देते हैं, ख़ासकर कम रैंक वाले देशों में असमानताओं को दूर करने पर। यह स्टडी यह समझने में मदद करती है कि सिविक एजुकेशन को असरदार तरीके से कैसे लागू और रिसर्च किया जा सकता है, जो पॉलिसीमेकर्स और एजुकेटर्स को दुनिया भर में सिविक एजुकेशन सिस्टम को मज़बूत करने के लिए इनसाइट देता है। इन नतीजों के प्रैक्टिकल असर बताते हैं कि पॉलिसी बनाने वाले और शिक्षक इन जानकारियों का इस्तेमाल करके ऐसे सिविक एजुकेशन प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं जो संदर्भ के हिसाब से काम के हों और मौजूदा एजुकेशनल कमियों को पूरा कर सकें।

(सुरियामन, एट अल. 2024) 21वीं सदी को ऐसी नई सिविक एजुकेशन की ज़रूरत है जो पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़े और लोगों को एक्टिव, जानकारी रखने वाले और ज़िम्मेदार नागरिक बनने में मदद करे। समस्या यह है कि 21वीं सदी में, एक इंटीग्रेटेड नॉलेज सिस्टम के तौर पर, सिविक एजुकेशन की मौजूदा स्थिति लोगों को एक खुले डेमोक्रेटिक समाज में एक्टिव पार्टिसिपेंट बनने के लिए तैयार करने के महत्व को पहचानती है। एक इंटीग्रेटेड नॉलेज सिस्टम को अपनाकर सिविक एजुकेशन के ज़रिए यह देश की आने वाली पीढ़ियों को एक ज़्यादा न्यायपूर्ण, समान और टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए ज़रूरी सिस्टम और समझ से लैस कर सकता है। इस स्टडी का मक़सद स्टूडेंट्स को सिविक एंगेजमेंट के लिए ज़रूरी नॉलेज, स्किल्स और नज़रिये से लैस करने की कोशिशों का एक ओवरव्यू देना है यह तरीका ऐसे जानकारी रखने वाले और ज़िम्मेदार नागरिक बनाने की कोशिश करता है जो स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में पॉज़िटिव योगदान दें। यह रिसर्च लिटरेचर रिव्यू मेथड के साथ एक क्वालिटेटिव अप्रोच का इस्तेमाल करती है। इस एनालिसिस के नतीजे दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स को ऐसे नागरिक के तौर पर तैयार करने के लिए सिविक एजुकेशन सीखने के तरीक़े में सुधार की ज़रूरत है, जो आज की सोशल कॉम्प्लेक्सिटी में एक इंटीग्रेटेड हिस्से के तौर पर नॉलेज, स्किल्स और नज़रिये से शुरू होकर 21वीं सदी में आगे बढ़ें और डेवलप हों। नागरिकों को 21वीं सदी की स्किल-बेस्ड एजुकेशन के ज़रिए ज़्यादा सुधारवादी नज़रिये के साथ तैयार रहना चाहिए।

यद्यपि उपर्युक्त अध्ययनों ने शक्ति परिवर्तन, राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय रणनीतियों का विश्लेषण किया है, तथापि 21वीं सदी में राजनीतिक पुनर्गठन को बहु-सैद्धांतिक ढाँचे (यथार्थवाद, उदारवाद, संरचनावाद और जटिल परस्पर निर्भरता) के समेकित दृष्टिकोण से देखने वाले अध्ययन सीमित हैं। विशेषकर भारत जैसे उभरते शक्ति-राज्य के संदर्भ में यह विश्लेषण अपर्याप्त रहा है। यह शोध-पत्र इसी अंतराल को भरने का प्रयास करता है।

3. सैद्धांतिक रूपरेखा

21वीं सदी में राजनीतिक पुनर्गठन की प्रक्रिया को समझने के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सिद्धांतों का विश्लेषण आवश्यक है। वैश्विक राजनीति केवल सैन्य शक्ति या आर्थिक संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विचारधाराओं, पहचान, संस्थागत संरचनाओं तथा पारस्परिक निर्भरता जैसे तत्वों से भी प्रभावित होती है। इस शोध में राजनीतिक पुनर्गठन को समझने के लिए प्रमुख रूप से यथार्थवाद, उदारवाद, संरचनावाद तथा जटिल पारस्पर निर्भरता की अवधारणाओं को आधार बनाया गया है।

(क) यथार्थवाद (Realism) और शक्ति संतुलन

यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसके अनुसार विश्व व्यवस्था अराजक (Anarchic) होती है और इसमें कोई सर्वोच्च वैश्विक सरकार नहीं होती। इस कारण प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्रीय हित, शक्ति संचय और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। 21वीं सदी में अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा, रूस–यूक्रेन संघर्ष तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती सैन्य सक्रियता इस सिद्धांत की प्रासंगिकता को दर्शाती है। शक्ति संतुलन की अवधारणा के अनुसार यदि कोई राष्ट्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है, तो अन्य राष्ट्र उसके प्रभाव को संतुलित करने हेतु गठबंधन बनाते हैं। इस प्रकार राजनीतिक पुनर्गठन को शक्ति संतुलन स्थापित करने के प्रयास के रूप में समझा जा सकता है।

(ख) उदारवाद (Liberalism) और संस्थागत सहयोग

उदारवाद इस बात पर बल देता है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ, आर्थिक सहयोग और लोकतांत्रिक मूल्य विश्व शांति और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र केवल प्रतिस्पर्धा में नहीं उलझे रहते, बल्कि वे पारस्परिक लाभ हेतु सहयोग भी करते हैं। 21वीं सदी में विश्व व्यापार संगठन (WTO), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र तथा G-20 जैसे मंचों की सक्रिय भूमिका यह दर्शाती है कि राजनीतिक पुनर्गठन में बहुपक्षीय संस्थाओं का महत्व बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक व्यापार और महामारी जैसी चुनौतियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि सहयोग के बिना वैश्विक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है।

(ग) संरचनावाद (Constructivism) और पहचान की भूमिका

संरचनावाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति केवल भौतिक शक्ति पर आधारित नहीं होती, बल्कि विचारों, सामाजिक मानदंडों, पहचान और धारणाओं से भी प्रभावित होती है। राष्ट्रों की नीतियाँ उनके ऐतिहासिक अनुभव, सांस्कृतिक मूल्यों और वैचारिक दृष्टिकोण से निर्मित होती हैं। उदाहरण के लिए, भारत की "राजनीतिक स्वायत्तता" की नीति, चीन का "शांतिपूर्ण उदय" का विमर्श, और यूरोपीय संघ की मानवाधिकार-आधारित विदेश नीति यह दर्शाती है कि पहचान और विचारधाराएँ राजनीतिक पुनर्गठन को प्रभावित करती हैं।

(घ) जटिल पारस्पर निर्भरता (Complex Interdependence)

जटिल पारस्पर निर्भरता की अवधारणा के अनुसार आधुनिक विश्व में राष्ट्र आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक-दूसरे पर निर्भर हैं। वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ, डिजिटल नेटवर्क, ऊर्जा निर्भरता और वित्तीय बाजार इस पारस्परिक निर्भरता को दर्शाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार युद्ध और शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त सहयोग और पारस्परिक हितों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए, 21वीं सदी का राजनीतिक पुनर्गठन केवल सैन्य संतुलन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों का मिश्रण है।

4. 21वीं सदी के राजनीतिक पुनर्गठन के प्रमुख आयाम

21वीं सदी में राजनीतिक पुनर्गठन बहुस्तरीय और बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में विकसित हुआ है। वैश्वीकरण, तकनीकी क्रांति, शक्ति संतुलन में परिवर्तन और उभरती सुरक्षा चुनौतियों ने राष्ट्रों तथा कॉरपोरेट संस्थाओं को अपनी नीतियों, संरचनाओं और रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बाध्य किया है। इस संदर्भ में भू-राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य–सुरक्षा तथा कॉरपोरेट–डिजिटल आयाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

(क) भू-राजनीतिक पुनर्गठन

21वीं सदी में वैश्विक शक्ति संरचना एकध्रुवीय से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर अग्रसर हुई है। शीत युद्ध के पश्चात

जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व प्रमुख था, वहीं अब चीन और भारत जैसी उभरती शक्तियाँ वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। चीन की *बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)* ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भू-राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाया है। वहीं, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में *क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग (QUAD)* जैसे मंचों की सक्रियता शक्ति संतुलन को नया स्वरूप दे रही है। रूस–यूक्रेन संघर्ष ने भी वैश्विक गठबंधनों और ऊर्जा राजनीति को पुनर्गठित किया है, जिससे यूरोप की सुरक्षा नीति और नाटो की भूमिका पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार भू-राजनीतिक पुनर्गठन का तात्पर्य केवल शक्ति संतुलन से नहीं, बल्कि क्षेत्रीय गठबंधनों, रणनीतिक साझेदारियों और वैश्विक प्रभाव क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण से भी है।

(ख) आर्थिक पुनर्गठन

वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन 21वीं सदी के राजनीतिक पुनर्गठन का एक प्रमुख आयाम है। वैश्वीकरण के प्रारंभिक चरण में मुक्त व्यापार और आपूर्ति शृंखलाओं का विस्तार हुआ, किंतु हाल के वर्षों में "आत्मनिर्भरता", "री-शोरिंग" और "फ्रेंड-शोरिंग" जैसी अवधारणाएँ प्रमुख हो गई हैं। कोविड-19 महामारी और भू-राजनीतिक तनावों ने वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं की कमजोरियों को उजागर किया। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रों ने उत्पादन और व्यापार नीति में विविधीकरण की रणनीति अपनाई। उदाहरणस्वरूप, *ब्रिक्स (BRICS)* देशों की आर्थिक भागीदारी वैश्विक आर्थिक संतुलन में परिवर्तन का संकेत देती है। इसके अतिरिक्त, मुक्त व्यापार समझौतों, क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारियों तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार ने आर्थिक रणनीतियों को नया रूप दिया है। भारत ने "आत्मनिर्भर भारत" जैसी पहल के माध्यम से घरेलू उद्योगों को सुदृढ़ करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है।

(ग) सैन्य एवं सुरक्षा पुनर्गठन

21वीं सदी में सुरक्षा की अवधारणा पारंपरिक सैन्य संघर्ष से आगे बढ़कर बहुआयामी हो गई है। अब सुरक्षा में साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और जैव-सुरक्षा जैसे आयाम भी शामिल हैं। अमेरिका और चीन के बीच सैन्य प्रतिस्पर्धा, रूस–यूक्रेन युद्ध तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में नौसैनिक गतिविधियाँ सैन्य पुनर्गठन को स्पष्ट करती हैं। *नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइज़ेशन (NATO)* ने अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को अद्यतन किया है, जबकि एशियाई क्षेत्र में नई रक्षा साझेदारियाँ उभर रही हैं। भारत ने भी रक्षा आधुनिकीकरण, स्वदेशी हथियार निर्माण और अंतरराष्ट्रीय रक्षा सहयोग के माध्यम से अपनी सुरक्षा नीति को पुनर्गठित किया है। इसके अतिरिक्त, साइबर युद्ध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित रक्षा प्रणालियाँ 21वीं सदी की सुरक्षा रणनीति का अभिन्न अंग बन चुकी हैं।

(घ) कॉरपोरेट एवं डिजिटल राजनीति

राजनीतिक पुनर्गठन केवल राष्ट्रों तक सीमित नहीं है; बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ और डिजिटल मंच भी अपनी रणनीतियों का पुनर्गठन कर रहे हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्स, डेटा प्रबंधन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने व्यापार और शासन की प्रकृति को बदल दिया है। गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी वैश्विक कंपनियाँ डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से वैश्विक शक्ति संरचना में अप्रत्यक्ष भूमिका निभा रही हैं। डिजिटल राजनीति में साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण कानून, डिजिटल संप्रभुता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रतिस्पर्धा शामिल है। यूरोपीय संघ का डिजिटल विनियमन मॉडल और भारत का डेटा संरक्षण कानून यह दर्शाते हैं कि डिजिटल क्षेत्र भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 21वीं सदी का राजनीतिक पुनर्गठन एक समग्र और बहुस्तरीय प्रक्रिया है। भू-राजनीतिक स्तर पर शक्ति संतुलन और गठबंधनों का पुनर्निर्धारण हो रहा है; आर्थिक स्तर पर व्यापार और उत्पादन संरचनाओं का पुनर्गठन हो रहा है; सैन्य एवं सुरक्षा स्तर पर नई तकनीकों और बहुआयामी खतरों को ध्यान

में रखते हुए नीतियाँ बदली जा रही हैं; तथा कॉरपोरेट और डिजिटल क्षेत्र में डेटा और तकनीकी प्रतिस्पर्धा नई राजनीतिक दिशा तय कर रही है। अतः यह स्पष्ट है कि 21वीं सदी में राजनीतिक पुनर्गठन केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और डिजिटल संरचना के व्यापक परिवर्तन का द्योतक है।

5. भारत के संदर्भ में राजनीतिक पुनर्गठन

21वीं सदी में वैश्विक शक्ति-संतुलन, तकनीकी क्रांति, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा चुनौतियों ने विश्व राजनीति की संरचना को गहराई से प्रभावित किया है। इस परिवर्तित परिदृश्य में भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और वैश्विक मंच पर प्रभावशाली भूमिका निभाने के उद्देश्य से व्यापक राजनीतिक पुनर्गठन किया है। यह पुनर्गठन केवल विदेश नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक नीति, रक्षा–सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी विकास, समुद्री शक्ति तथा वैश्विक साझेदारियों तक विस्तृत है। भारत की राजनीतिक सोच अब पारंपरिक गुटनिरपेक्षता से आगे बढ़कर "राजनीतिक स्वायत्तता" की अवधारणा पर आधारित है, जिसके अंतर्गत भारत किसी एक शक्ति-गुट पर निर्भर हुए बिना अपने हितों के अनुसार बहुआयामी संबंध स्थापित करता है।

(क) विदेश नीति और भू-राजनीतिक पुनर्गठन

21वीं सदी में भारत की विदेश नीति अधिक सक्रिय, बहुस्तरीय और परिणामोन्मुखी हुई है। भारत ने "पड़ोसी पहले" नीति के माध्यम से दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही "एक्ट ईस्ट नीति" के अंतर्गत दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक संबंधों को सुदृढ़ किया गया है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की सक्रियता यह दर्शाती है कि वह समुद्री मार्गों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है। भारत ने बहुपक्षीय मंचों में अपनी भागीदारी बढ़ाकर स्वयं को वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में प्रस्तुत किया है। जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर भारत की भूमिका निरंतर सशक्त हुई है।

(ख) आर्थिक पुनर्गठन और आत्मनिर्भरता

वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान और आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने भारत को अपनी उत्पादन क्षमता और औद्योगिक संरचना को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। "आत्मनिर्भर भारत" की अवधारणा के अंतर्गत विनिर्माण, कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त, बुनियादी ढाँचे के विकास जैसे बंदरगाह, राजमार्ग, रेल नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे भारत वैश्विक व्यापार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके। डिजिटल भुगतान प्रणाली, वित्तीय समावेशन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी पहलों ने आर्थिक संरचना को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाया है।

(ग) रक्षा और सुरक्षा पुनर्गठन

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। पारंपरिक थल-सीमा सुरक्षा के साथ-साथ समुद्री, साइबर और अंतरिक्ष सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। रक्षा आधुनिकीकरण के तहत उन्नत हथियार प्रणालियों, मिसाइल तकनीक, ड्रोन, साइबर सुरक्षा तंत्र और अंतरिक्ष निगरानी क्षमताओं का विकास किया गया है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देकर भारत ने आयात पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, रणनीतिक साझेदारियाँ और समुद्री सहयोग कार्यक्रम भारत की बढ़ती सामरिक सक्रियता को दर्शाते हैं। आतंकवाद, सीमा

विवाद, समुद्री डकैती, साइबर अपराध और हाइब्रिड युद्ध जैसी नई चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी सुरक्षा दृष्टिकोण अपनाया गया है।

(घ) कॉरपोरेट एवं डिजिटल राजनीति

21वीं सदी की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में डिजिटल तकनीक निर्णायक कारक बन चुकी है। भारत ने डिजिटल अवसंरचना, डेटा प्रबंधन और ई-गवर्नेंस को राजनीतिक प्राथमिकता दी है। "डिजिटल इंडिया" अभियान के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल पहचान प्रणाली, ऑनलाइन सेवाएँ और साइबर सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास ने भारत को वैश्विक नवाचार मानचित्र पर स्थापित किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5G तकनीक, सेमीकंडक्टर निर्माण और हरित प्रौद्योगिकी में निवेश भारत की दीर्घकालिक राजनीतिक सोच को दर्शाता है। कॉरपोरेट क्षेत्र में वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधार, कर सुधार और व्यापार सुगमता उपाय लागू किए गए हैं, जिससे भारत को वैश्विक उत्पादन और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके।

भारत का राजनीतिक पुनर्गठन बहुआयामी, संतुलित और भविष्य-उन्मुख है। यह पुनर्गठन तीन प्रमुख उद्देश्यों पर आधारित प्रतीत होता है:

- राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा
- आर्थिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता
- वैश्विक मंच पर प्रभावशाली और जिम्मेदार शक्ति के रूप में उभरना

21वीं सदी की बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत का यह राजनीतिक पुनर्गठन उसे एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह केवल परिस्थितियों की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय दृष्टि का परिणाम है।

6. चुनौतियाँ एवं सीमाएँ

21वीं सदी में राजनीतिक पुनर्गठन एक जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया है, जो अवसरों के साथ-साथ अनेक गंभीर चुनौतियाँ और संरचनात्मक सीमाएँ भी प्रस्तुत करती है। वैश्विक शक्ति संतुलन में परिवर्तन ने महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को तीव्र किया है। विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के मध्य उभरती राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को नए ध्रुवीकरण की ओर अग्रसर किया है। यह प्रतिस्पर्धा व्यापार, प्रौद्योगिकी, सैन्य विस्तार और क्षेत्रीय प्रभाव के क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिससे वैश्विक स्थिरता प्रभावित हो रही है।

इसके अतिरिक्त रूस और यूक्रेन के मध्य संघर्ष ने यूरोपीय सुरक्षा संरचना को पुनर्परिभाषित किया है तथा नाटो की भूमिका को पुनः सक्रिय किया है। इस प्रकार महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक अस्थिरता, ऊर्जा संकट और आर्थिक अनिश्चितता जैसी समस्याओं को जन्म दिया है।

आर्थिक दृष्टि से भी राजनीतिक पुनर्गठन अनेक सीमाओं से घिरा हुआ है। वैश्वीकरण के बावजूद संरक्षणवाद, व्यापार प्रतिबंधों और तकनीकी नियंत्रण की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं की कमजोरियों को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप "री-शोरिंग" और "फ्रेंड-शोरिंग" जैसी रणनीतियाँ सामने आईं। यद्यपि G20 और BRICS जैसे मंच वैश्विक आर्थिक संतुलन की दिशा में प्रयासरत हैं, फिर भी वैश्विक आर्थिक शासन में असमानता और विकासशील देशों की सीमित भागीदारी एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।

तकनीकी क्षेत्र में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी राजनीतिक पुनर्गठन की जटिलता को बढ़ाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5G, साइबर अवसंरचना और डेटा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा ने राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को विस्तृत कर दिया है। साइबर

हमले, डेटा उल्लंघन और सूचना युद्ध जैसी समस्याएँ नई प्रकार की असुरक्षा उत्पन्न कर रही हैं। डिजिटल संप्रभुता की अवधारणा के कारण राष्ट्र अपने डेटा और तकनीकी अवसंरचना को सुरक्षित करने के लिए कठोर कानून बना रहे हैं, किंतु वैश्विक स्तर पर साइबर शासन के लिए कोई सर्वमान्य ढाँचा विकसित नहीं हो सका है। यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय सहयोग की सीमाओं को दर्शाती है।

वैश्विक शासन संस्थाओं की संरचनात्मक सीमाएँ भी राजनीतिक पुनर्गठन की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएँ 20वीं सदी की शक्ति संरचना पर आधारित हैं, जबकि वर्तमान चुनौतियाँ कहीं अधिक जटिल और बहुआयामी हैं। सुरक्षा परिषद की संरचना, वीटो व्यवस्था और प्रतिनिधित्व की असमानता वैश्विक न्यायसंगतता पर प्रश्नचिह्न लगाती है। जलवायु परिवर्तन, महामारी और आतंकवाद जैसी समस्याओं के समाधान हेतु समन्वित वैश्विक प्रयास अपेक्षित हैं, किंतु राजनीतिक मतभेद और शक्ति-प्रतिस्पर्धा प्रभावी सहयोग में बाधा उत्पन्न करती हैं।

भारत के संदर्भ में भी राजनीतिक पुनर्गठन सरल नहीं है। सीमावर्ती तनाव, ऊर्जा निर्भरता, रक्षा आधुनिकीकरण की उच्च लागत तथा आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन के बीच संतुलन बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। बहुध्रुवीय विश्व में संतुलित कूटनीति अपनाते हुए "राजनीतिक स्वायत्तता" को बनाए रखना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए सतत अनुकूलन और विवेकपूर्ण नीति-निर्माण आवश्यक है। अतः स्पष्ट है कि राजनीतिक पुनर्गठन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसकी सफलता विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कारकों के संतुलन पर निर्भर करती है।

7. निष्कर्ष

21वीं सदी में राजनीतिक पुनर्गठन वैश्विक राजनीति का केंद्रीय तत्त्व बन चुका है। शीत युद्धोत्तर एकध्रुवीय व्यवस्था से बहुध्रुवीय शक्ति संरचना की ओर संक्रमण ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप को मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया है। यह परिवर्तन केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक संरचना, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, डिजिटल शासन, क्षेत्रीय गठबंधनों और वैश्विक संस्थागत सुधारों तक विस्तृत है। शक्ति का पारंपरिक स्वरूप अब बहुआयामी हो चुका है, जिसमें आर्थिक सामर्थ्य, तकनीकी नवाचार, डिजिटल अवसंरचना और वैचारिक प्रभाव समान रूप से महत्वपूर्ण हो गए हैं।

सैद्धांतिक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि यथार्थवाद शक्ति संतुलन और सुरक्षा प्रतिस्पर्धा की निरंतरता को रेखांकित करता है, जबकि उदारवाद और संरचनावाद सहयोग, संस्थागत ढाँचों तथा विचारधारात्मक तत्वों की भूमिका को उजागर करते हैं। 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति प्रतिस्पर्धा और सहयोग के इस सम्मिलित स्वरूप को प्रतिबिंबित करती है। महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय गठबंधनों का पुनर्गठन, आपूर्ति शृंखलाओं का विविधीकरण और तकनीकी प्रभुत्व की दौड़ ये सभी राजनीतिक पुनर्गठन की गतिशील प्रकृति को दर्शाते हैं।

भारत के संदर्भ में यह प्रक्रिया विशेष महत्व रखती है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत ने "राजनीतिक स्वायत्तता" के सिद्धांत के आधार पर संतुलित और बहुआयामी विदेश नीति अपनाई है। आर्थिक आत्मनिर्भरता, रक्षा आधुनिकीकरण, डिजिटल नवाचार और बहुपक्षीय सक्रियता के माध्यम से भारत स्वयं को एक जिम्मेदार और प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। यह पुनर्गठन केवल वैश्विक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय दृष्टि का परिणाम है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि 21वीं सदी का राजनीतिक पुनर्गठन एक सतत और अविरत प्रक्रिया है, जो बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ विकसित होती रहेगी। भविष्य की वैश्विक स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि राष्ट्र प्रतिस्पर्धा और सहयोग के बीच संतुलन स्थापित करने में कितने सफल होते हैं। यदि यह पुनर्गठन समावेशी,

न्यायसंगत और संस्थागत रूप से सुदृढ़ दिशा में आगे बढ़ता है, तो यह वैश्विक शांति, स्थिरता और सतत विकास के लिए आधार प्रदान कर सकता है; अन्यथा यह ध्रुवीकरण और अस्थिरता को और गहरा कर सकता है।

8. संदर्भ सूची

1. नाई, जे. एस. (2023). ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी पावर शिफ्ट्स को समझना. *सॉफ्ट पावर और ग्रेट-पावर कॉम्पिटिशन में* (पृ. 29–33). स्प्रिंगर।
2. दास, बी., एवं मो., एस. (2025). 21वीं सदी में भारत और पश्चिम एशिया के बीच स्ट्रैटेजिक संबंध: चुनौतियाँ और अवसर. *रिसर्च रिव्यू जर्नल ऑफ सोशल साइंस*, 5(1), 189–198।
3. राम, डॉ. गणेश (2020). भारत की विदेश नीति: 21वीं सदी में बदलते वैश्विक परिदृश्य की ओर अग्रसर. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस*, 2(2), 129–133।
4. गूच, एम. टी. आर., एवं डी. एम. (2015). ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी में सिविक एजुकेशन के आयाम: बेहतर थ्योरी, एनालिसिस और प्रैक्टिस की ओर आगे का रास्ता. एम. टी. रोजर्स एवं डी. एम. गूच (सं.). *ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी में सिविक एजुकेशन* (पृ. 455–488). लेक्सिंगटन बुक्स।
5. कूपर, टी. एल. (2005). ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी में सिविक एंगेजमेंट: एक स्कॉलरली और प्रैक्टिकल एजेंडा की ओर. *पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू*, 65(5), 534–535।
6. हार्ट, एम., एवं यूनिस, जे. (2017). 21वीं सदी में नागरिक विकास (वॉल्यूम 1). ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। https://doi.org/10.1093/oso/9780190641481.003.0007
7. कुह्न, यू. (2023). 21वीं सदी में स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी: एक परिचय. *जर्नल फॉर पीस एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट*, 6(1), 1–8।
8. आयरलैंड, आर. डी., एवं हिट, एम. ए. (1999). 21वीं सदी में स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस हासिल करना और बनाए रखना: स्ट्रैटेजिक लीडरशिप की भूमिका. *अकैडमी ऑफ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव्स*, 13(1), 43–57।
9. सॉन्ग, डब्ल्यू. (2022). स्ट्रैटेजिक मौके की खिड़की का फ़ायदा उठाना: 21वीं सदी के बाद से चीन के मैक्रो-स्ट्रैटेजिक नैरेटिव का एक अध्ययन. *सोशल साइंसेज*, 11(10), 461।
10. सुमारोटो, एस., हेंड्रिया, बी., एवं सोहाटो, एस. (2024). 21वीं सदी में नागरिक शिक्षा: विद्वानों के ट्रेंड्स का एक बिब्लियोमेट्रिक विश्लेषण. *ताद्रिस: जर्नल कगुरुआन दान इल्मु तरबियाह*, 9(2), 569–582।
11. सुरियामन, एस., कोमलसारी, के., नुर्गियांसाह, टी. एच., प्रयोगी, आर., एवं ब्रीबिन, एम. एल. (2024). 21वीं सदी में एक इंटीग्रेटेड नॉलेज सिस्टम के तौर पर नागरिक शिक्षा: एक सुधार का तरीका. *JED (जर्नल एटिका डेमोक्रेसी)*, 9(3), 423–443।